

प्रेषक,

एन10एस10नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवागें,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 2 मई, 2008

विषय:- मै0 उत्तराखण्ड उदय ट्रस्ट रुड़की को पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम धनौरी में कुल 2.188 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1234/भूमि व्यवस्था भूमि कय VIII दिनांक 16-11-2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 उत्तराखण्ड उदय ट्रस्ट रुड़की को पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम धनौरी में माप/ख0र10 339/2 रकबा 1.810 है0 एवं 341 गे रकबा 0.3080 है0 अर्थात् कुल 2.188 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ प्रदान करते हैं:

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बंधक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लागों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

.....(2)

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त 180 दिन के भीतर योजना का निर्माण कार्य आरम्भ करा लिया जायेगा।
- 7- संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग पोलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट (तकनीकी संस्थान) की स्थापना हेतु कर लिया जायेगा।
- 8- संस्था द्वारा उत्तराखण्ड गूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत का रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पोलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु नियमानुसार नियत प्राधिकारी को आवेदन कर दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन करा लिया जायेगा।
- 11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 12- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेगी।
- 13- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०न०पल०व्याल)

प्रमुख सचिव।

.....(3)

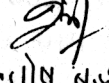
-३-

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- श्री अफरोज क्यूम, उत्तराखण्ड उदय ट्रस्ट, रुड़की, ग्राम-रुहालकी, पो0ओ0-  
शगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार।
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(सन्तोष बड़ोनी)  
अनुसचिव।